

## Kin 'carry' pregnant woman across river, NHRC intervenes

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued notices to the Collector of Kalahandi in Odisha over reports of a pregnant woman being carried on a cot across a river in the absence of a bridge. Acting on the petition of human rights activist Akhand, the NHRC directed that the Collector submit an action taken report within four weeks. The incident happened in December when family members of the pregnant woman in Khamanpada village contacted an ambulance when she went into labour. However, as the ambulance could not reach the remote village, the kin had to carry the woman by a cot across the Indravati on a country boat.

## **NHRC sends notices over human trafficking**

NHRC has taken suo moto cognisance of a media report that Berhampur railway station in Ganjam district of Odisha has turned into a major transit point for human trafficking from Bihar to Andhra Pradesh. In 2022, a total of 343 children were rescued from the station. Accordingly, it has issued notices calling for reports within six weeks from the Chief Secretaries and Director Generals of Police of Bihar, Odisha and Andhra Pradesh, the Secretary, Union Ministry of Women and Child Development and the Chairman, Railway Board.

## **NHRC sends notices over human trafficking**

NHRC has taken suo moto cognisance of a media report that Berhampur railway station in Ganjam district of Odisha has turned into a major transit point for human trafficking from Bihar to Andhra Pradesh. In 2022, a total of 343 children were rescued from the station. Accordingly, it has issued notices calling for reports within six weeks from the Chief Secretaries and Director Generals of Police of Bihar, Odisha and Andhra Pradesh, the Secretary, Union Ministry of Women and Child Development and the Chairman, Railway Board.

## Pregnant woman carried on cot for 5 kms: NHRC issues notice

**STATESMAN NEWS SERVICE**

BHUBANESWAR, 10 JANUARY:

The National Human Rights Commission (NHRC) has asked the Kalahandi Collector to submit an Action Taken Report within four weeks on a report of a pregnant woman being carried on a cot by locals for at least five kilometres due to lack of road connectivity in a remote village.

The far-flung Ranipada village in Kalahandi district does not have road connectivity across two rivulets. In the absence of road connectivity, a pregnant woman was carried on a cot for five Kms through the two rivers to

**As luck would have it, the woman delivered a male child despite delayed hospitalization. The**

avail healthcare facility in Thaumal Rampur Community Health Centre on 30 December last. As luck would have it, the woman delivered a male child despite delayed hospitalization. The

The apex rights panel taking note of a petition filed by rights activist Akhand directed the Kalahandi district Collector to comply with ATR within four weeks of the receipt of the order.

**The Statesman**

Wed, 11 January 2023  
<https://epaper.thes>



## Team begins probe into 28 deaths in MCH

<https://www.newindianexpress.com/states/odisha/2023/jan/11/team-begins-probe-into-28-deaths-in-mch-2536786.html>

A four-member team from Koraput district health department on Tuesday began inquiry into the 28 deaths reported in three days during last week of November 2022 at Sahid Laxman Naik Medical College and Hospital (SLNMCH).

The team visited the facility following the National Human Rights Commission (NHRC) direction to the state government to inquire into the 28 deaths in just three days. The rights body issued the direction based on a complaint filed by advocate Anup Kumar Patro, a Jeypore-based human rights activist.

However, the hospital management had earlier clarified that all these patients were in critical condition and succumbed to different ailments. On the day, the team led by Koraput CDMO Arun Padhee visited the medical college and hospital and verified the death related documents. They also questioned the doctors who had treated the patients and superintendent Sitaram Mohapatra.

The CDMO will submit the report to the state government and the NHRC. It is learnt that the team found some discrepancies in the hospital slips given to patients during treatment which should have been clearly maintained, sources said, adding, due to NHRC intervention, the hospital staff and medical authorities are a worried lot.

As per reports, Patro had filed a complaint with NHRC alleging that 28 persons died while undergoing treatment in the SLN Hospital. While 13 persons died in the hospital on November 27, six on November 28 and the rest on November 29.

He had submitted that the patients died due to negligence of doctors and other staff and lack of timely intervention during treatment. The NHRC then issued a direction to the government, asking the chief medical officer of Koraput, collector and SP to look into the complaint and submit an action taken report within four weeks with the Commission. The SLNMCH caters to the healthcare needs of at least 4 districts of south Odisha. Over 700 patients visit the hospital daily.

**मुजफ्फरपुर किडनी कांड • सुनवाई के बाद आदेश**

## एनएचआरसी ने मुख्य सचिव व डीजीपी से कहा- कार्रवाई करें

भास्कर न्यूज़ | मुजफ्फरपुर

**4 हफ्ते में मांगा था जवाब**

जिले में चर्चित किडनी कांड के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुख्य सचिव व डीजीपी को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। इस बाबत जिलाधिकारी व एसएसपी से रिपोर्ट तलब करते हुए चार सप्ताह में जवाब मांगा है। पीड़ित महिला सुनीता देवी की ओवरी के ऑपरेशन के दौरान दोनों किडनी निकालने का मामला प्रकाश में आने के बाद मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व राज्य मानवाधिकार आयोग में याचिका दाखिल की थी।

मामले में एनएचआरसी ने सभी को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा था। तब डीएम व एसएसपी ने अपनी रिपोर्ट में एफआईआर दर्ज कर जांच की बात कही थी। रिपोर्ट पर सुनवाई करते हुए आयोग ने एसएसपी से वर्तमान स्थिति व पीड़िता को मुआवजा दिए जाने से जुड़ी रिपोर्ट की मांग की है।

और मामले में संलिप्त आरोपितों की अविलम्ब गिरफ्तारी की मांग की थी। सुनवाई करते हुए आयोग ने यह कार्रवाई की है।



## दो दिवसीय शिविर आयोजित करेगा एनएचआरसी

नई दिल्ली, (भाषा)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग महाराष्ट्र में मानवाधिकार उल्लंघन के लंबित मामलों की सुनवाई के लिए बुधवार को मुंबई में दो दिवसीय शिविर आयोजित करेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की ओर से मंगलवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि राज्य के अधिकारियों और संबंधित शिकायतकर्ताओं को भी सुनवाई में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। एनएचआरसी के सदस्य डी.एम. मुले बुधवार को सह्याद्री स्टेट गेस्ट हाउस में एनएचआरसी सदस्य राजीव जैन व वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में बैठक कर शिविर की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे लंबित मामलों की सुनवाई करेंगे। एनएचआरसी ने कहा, मामले बिजली विभाग की लापरवाही के कारण मौत, सेवानिवृत्ति के लाभ से इनकार, नागपुर सेंट्रल जेल में अनियमितता, कोली समुदाय से संबंधित लोगों के मौलिक मानवाधिकारों की रक्षा में कथित लापरवाही, एक इमारत गिरने से 11 लोगों की मौत और बाल मजदूरों से जुड़ी बंधुआ श्रम की घटनाओं आदि से संबंधित है।

## मानवाधिकारों के उल्लंघन के लंबित मामलों की सुनवाई के लिए NHRC मुंबई में दो दिवसीय शिविर आयोजित करेगा

<https://jantaserishta.com/world/nhrc-to-hold-two-day-camp-in-mumbai-to-hear-pending-cases-of-human-rights-violations-1917746>

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग महाराष्ट्र में कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन के लंबित मामलों की सुनवाई के लिए बुधवार से मुंबई में दो दिवसीय शिविर आयोजित करेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि राज्य के अधिकारियों और संबंधित शिकायतकर्ताओं को भी ऑन-स्पॉट विचार-विमर्श की सुविधा के लिए सुनवाई में उपस्थित होने के लिए कहा गया है।

बयान में कहा गया है कि मामलों की सुनवाई के अलावा, दो दिवसीय शिविर बैठक का उद्देश्य राज्य के अधिकारियों को मानवाधिकारों के बारे में संवेदनशील बनाना और गैर सरकारी संगठनों और मानवाधिकार रक्षकों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करना है। एनएचआरसी सदस्य डीएम मुले बुधवार को सहयाद्री स्टेट गेस्ट हाउस में एनएचआरसी सदस्य राजीव जैन व वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में बैठक कर शिविर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे लंबित मामलों की सुनवाई करेंगे।

"मामले बिजली विभाग की लापरवाही के कारण मौत, सेवानिवृत्ति के लाभ से इनकार, नागपुर सेंट्रल जेल में अनियमितता, 'कोली' समुदाय से संबंधित लोगों के मौलिक मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कथित लापरवाही, एक इमारत गिरने से ग्यारह लोगों की मौत से संबंधित हैं।" एनएचआरसी ने कहा, बाल मजदूरों से जुड़े बंधुआ श्रम की घटनाएं आदि।

गुरुवार को आयोग गैर सरकारी संगठनों और मानवाधिकार रक्षकों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगा। उसके बाद, राज्य के मानवाधिकारों के मुद्दों और उसके द्वारा की गई कार्रवाइयों की जानकारी का व्यापक प्रसार करने के लिए आयोग बैठक के परिणाम के बारे में मीडिया को जानकारी देगा। इस तरह की सुनवाई मानव अधिकारों के उल्लंघन के शिकार लोगों को त्वरित न्याय के लिए एक मंच प्रदान करती है। 2007 से, आयोग ने अब तक उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, गुजरात, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मध्य प्रदेश, पंजाब, केरल, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, झारखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शिविर बैठकें आयोजित की हैं। , नागालैंड, उत्तराखंड, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, यह कहा।



News24 Hindi/ हिन्दुस्थान समाचार

## **Bihar News : किडनी कांड : NHRC ने बिहार के मुख्य सचिव व डीजीपी को नोटिस जारी कर मांगा ये जवाब**

<https://hindi.news24online.com/state/bihar/nhrc-issued-notice-chief-secretary-and-dgp/126884/>

<https://www.hindusthansamachar.in/Encyc/2023/1/10/NHRC-Action-against-kidney-case-in-muzaffarpur.php>

जिले के चर्चित सुनीता किडनी कांड मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव व डीजीपी को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी व एसएसपी से रिपोर्ट तलब करते हुए चार सप्ताह में जवाब माँगा है।

यह है मामला

पीड़ित महिला सुनीता देवी के ऑपरेशन के दौरान दोनों किडनी निकालने का मामला प्रकाश में आने के बाद मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के. झा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राज्य मानवाधिकार आयोग में याचिका दाखिल की थी और मामले में संलिप्त आरोपितों की अविलम्ब गिरफ्तारी की माँग की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने यह कार्रवाई की है। जिले के सकरा थाने के मथुरापुर गाँव की निवासी सुनीता देवी को पेट में दर्द था, जिसका इलाज बरियारपुर के शुभकान्त क्लिनिक में एक झोलाछाप चिकित्सक पवन कुमार के द्वारा किया गया। डॉक्टर पवन कुमार ने महिला के गर्भाशय में ट्यूमर होने की बात कही और 3 सितम्बर को महिला का ऑपरेशन किया।

सीटी स्कैन में दोनो किडनी मिली गायब

ऑपरेशन के बाद सुनीता की तबीयत बिगड़ने लगी, शरीर में सूजन आने लगी। तब जाकर महिला के परिजनों के द्वारा मुजफ्फरपुर के एस.के.एम.सी.एच. में सुनीता का सीटी स्कैन कराया गया। रिपोर्ट में दोनो किडनी गायब थी, ऑपरेशन के दौरान किडनी गायब होने की एफआईआर दर्ज कराने के बाद प्रशासनिक अधिकारी सकते में आये और जाँच शुरू हुई, तब मालूम चला कि उक्त क्लिनिक सरकार के मानदंड के अंतर्गत कार्य नहीं कर रहा है।

आयोग ने स्वास्थ्य सचिव को दिया नोटिस

इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा पूर्व में बिहार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव, मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी व एसएसपी को नोटिस जारी किया गया था और चार सप्ताह में जवाब माँगा गया था। जिले के जिलाधिकारी व एसएसपी द्वारा आयोग में रिपोर्ट

प्रेषित की गयी थी जिसमें मामले में एफआईआर दर्ज कर अनुसन्धान किये जाने की बात कही गयी थी। रिपोर्ट पर सुनवाई करते हुए आयोग ने एसएसपी मुजफ्फरपुर से अनुसन्धान की वर्तमान स्थिति व जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर से पीड़िता को मुआवजा दिए जाने से जुड़ी रिपोर्ट की माँग की है।

सरकार से मदद की आस

मामले के सम्बन्ध में मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के. झा ने कहा कि यह काफी गंभीर मामला है और इस मामले में बिना विलम्ब किये सरकार को अच्छे चिकित्सा संस्थान में पीड़ित महिला का ईलाज सुनिश्चित करना चाहिए। तथा किडनी प्रत्यारोपण के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए, क्योंकि पीड़ित महिला कि जान बचाने की दिशा में सरकार को हरसंभव प्रयास करने की जरूरत है।

## **NHRC sends notices over human trafficking**

NHRC has taken suo moto cognisance of a media report that Berhampur railway station in Ganjam district of Odisha has turned into a major transit point for human trafficking from Bihar to Andhra Pradesh. In 2022, a total of 343 children were rescued from the station. Accordingly, it has issued notices calling for reports within six weeks from the Chief Secretaries and Director Generals of Police of Bihar, Odisha and Andhra Pradesh, the Secretary, Union Ministry of Women and Child Development and the Chairman, Railway Board.

## NCW: राष्ट्रीय महिला आयोग ने जेल अधिकारियों के साथ की बैठक, कैदियों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का आह्वान

<https://www.amarujala.com/india-news/ncw-organised-meeting-on-women-prisoners-rights-with-dgs-igs-of-prisons-several-suggestions-made-for-inmates>

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने महिला कैदियों के अधिकारों को लेकर शीर्ष जेल अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें अधिक से अधिक जेल कर्मचारियों की तैनाती, कैदियों की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने और जेल के बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के सुझाव सामने आए।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि एनसीडब्ल्यू ने जेलों में महिला कैदियों के कल्याण को प्रभावित करने वाले प्रावधानों पर चर्चा करने के लिए सोमवार को देशभर के जेल महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के साथ 'महिला कैदियों के अधिकारों के आलोक में पुलिस प्रशासन' विषय पर बैठक की। इसमें जेलों के लगभग 16 डीजी/आईजी और राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, गैर सरकारी संगठनों और शिक्षाविदों ने भाग लिया। बयान में कहा गया है कि बैठक के दौरान, महिला कैदियों की स्थिति में सुधार के लिए कई सुझाव दिए गए।

बैठक में मिले सुझाव

बयान के मुताबिक, इन सुझावों में अधिक से अधिक जेल कर्मचारियों की तैनाती, कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना, जेलों की बुनियादी सुविधाओं की समस्याओं को दूर करना, कैदियों को गुणवत्तापूर्ण कानूनी सहायता प्रदान करना और उनके लिए मजबूत व्यावसायिक प्रशिक्षण सुनिश्चित करना शामिल थे।

महिला कैदियों को सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हों...

बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने यह सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया कि जेलों में महिला कैदियों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। उन्होंने डीजी (जेल) से आह्वान किया कि जेल से रिहा होने के बाद इन महिलाओं को उनके परिवारों और समाज के साथ आर्थिक पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जाए।

मुंबई में दो दिवसीय शिविर आयोजित करेगा एनएचआरसी

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) महाराष्ट्र में मानवाधिकार उल्लंघन के लंबित मामलों की सुनवाई के लिए बुधवार को मुंबई में दो दिवसीय शिविर आयोजित करेगा। एनएचआरसी की ओर से मंगलवार को जारी एक बयान में कहा गया कि राज्य के अधिकारियों और संबंधित शिकायतकर्ताओं को भी सुनवाई में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। एनएचआरसी के सदस्य डी.एम. मुले बुधवार को सहाय्यी स्टेट गेस्ट हाउस में एनएचआरसी सदस्य राजीव जैन व वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में बैठक कर शिविर की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे लंबित मामलों की सुनवाई करेंगे।

## **Kin carry pregnant woman across river in Odisha; NHRC intervenes**

<https://www.thehindu.com/news/national/other-states/pregnant-woman-carried-on-cot-in-a-country-boat-to-cross-river-in-odisha/article66361338.ece>

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued notices to the District Collector of Odisha's Kalahandi over reports of a pregnant woman being carried on a cot to cross a river in the absence of a bridge.

Acting on the petition of human rights activist Akhand, the NHRC directed the District Collector submit an action taken report (ATR) within four weeks.

The incident took place Khamanpada village under the Thuamula Rampur block of Kakandi. Khamanpada is about 25 km from the block headquarter town.

Family members of the pregnant woman, identified as Droupadi Gouda, contacted an ambulance service when she experienced labour pain in the month of December. The ambulance could not reach the remote Khamanpada village, leaving family members with no option but to carry Ms. Gouda by a cot across the Indravati river in a country boat before availing the ambulance. The woman gave birth to a boy. Villagers face such crises nature every day.

Several villages in Kalahandi district do not have road connectivity. Pregnant women of 16 villages under the N. Podapadar Gram Panchayat, encircled by the vast water body of the Indravati reservoir, face similar difficulties.

Recently, Lanjigarh block authorities had come up with a unique solution when laying an all-weather road to habitations situated on hilltops. As many as 16 families belonging to Kutia Kondh tribe of Barguda village were persuaded to climb down and start living at the foothill, from where they can more easily access basic amenities for health and education, and other government programmes. They were allotted houses under the Prime Minister Awas Yojana (PMAY). Similarly, Kotia Kondh tribals from the Bhedapati hill village also moved to the foothill.



Press Trust of India/ Mid-Day/ Lokmat/ ThePrint/ Newsdrum/ Latestly/ Devdiscourse

## **NHRC to hold two-day camp in Mumbai to hear pending cases of human rights violations**

<https://www.ptinews.com/news/north/nhrc-to-hold-two-day-camp-in-mumbai-to-hear-pending-cases-of-human-rights-violations/491733.html>

<https://www.mid-day.com/news/india-news/article/nhrc-to-hold-two-day-camp-in-mumbai-to-hear-pending-cases-of-human-rights-violations-23264799>

<https://www.lokmatimes.com/maharashtra/nhrc-to-hold-two-day-camp-sitting-in-mumbai-to-hear-pending-cases-of-alleged-human-rights-violations/>

<https://theprint.in/india/nhrc-to-hold-two-day-camp-in-mumbai-to-hear-pending-cases-of-human-rights-violations/1308004/>

<https://www.newsdrum.in/national/nhrc-to-hold-two-day-camp-in-mumbai-to-hear-pending-cases-of-human-rights-violations>

<https://www.latestly.com/agency-news/india-news-nhrc-to-hold-two-day-camp-in-mumbai-to-hear-pending-cases-of-human-rights-violations-4695241.html>

<https://www.devdiscourse.com/article/law-order/2314579-nhrc-to-hold-two-day-camp-in-mumbai-to-hear-pending-cases-of-human-rights-violations>

The National Human Rights Commission will hold a two-day camp sitting in Mumbai from Wednesday to hear pending cases of alleged human rights violations in Maharashtra, a senior official said.

The state authorities and the complainants concerned have also been asked to be present at the hearing to facilitate on-spot deliberations, the National Human Rights Commission (NHRC) said in a statement on Tuesday.

Besides hearing cases, the aim of the two-day camp sitting is to sensitise the state officials about human rights and interact with the representatives of NGOs and human rights defenders, it said in the statement.

NHRC Member DM Mulay will inaugurate the camp sitting in the presence of NHRC Member Rajiv Jain and senior officers at Sahyadri State Guest House on Wednesday. Thereafter, they will hear the pending cases, it added.

"The cases relate to death due to negligence of the electricity department, denial of retiral benefits, irregularities in Nagpur Central Jail, alleged negligence to protect the fundamental human rights of people belonging to 'Koli' community, death of eleven people in a building collapse, incidents of bonded labour involving child labourers, etc," the NHRC said.

On Thursday, the commission will meet representatives of NGOs and human rights defenders. After that, the commission will brief the media about the outcome of the camp sitting in order to have a wider dissemination of information on human rights issues of the state and the actions taken by it.

Such hearings provide a platform for speedy justice to victims of human rights violations. Starting from 2007, the commission has so far held camp sittings in Uttar Pradesh, Bihar, Karnataka, Odisha, Gujarat, Assam, Meghalaya, Chhattisgarh, Manipur, Madhya Pradesh, Punjab, Kerala, Puducherry, Andhra Pradesh, Jharkhand, Andaman & Nicobar Islands, Nagaland, Uttarakhand, Rajasthan, Arunachal Pradesh, West Bengal and Tamil Nadu, it said.